

कार्यसूची सं.	1
बैठक का दिनांक	15.05.2018
बैठक सं.	63

दिनांक 13 फरवरी, 2018 को आयोजित 62 वीं SLBC बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

- दिनांक 13 फरवरी, 2018 को आयोजित 62 वीं एस एल बी सी बैठक के कार्यवृत्त सभी संबंधित कार्यालयों को संप्रेषित किए गए हैं।
- सभा के द्वारा उपर्युक्त बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है क्योंकि इस संबंध में किसी भी कार्यालय /विभाग द्वारा किसी प्रकार के संशोधन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

कार्यसूची सं.	2
बैठक का दिनांक	15.05.2018
बैठक सं.	63

पूर्व मे आयोजित एस एल बी सी बैठक में लिये गये निर्णय पर कृत रिपोर्ट

राज्य सरकार से संबंधित मामले

क्र.स.	से लंबित	विषय	झारखण्ड सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्तमान स्थिति
3.1.1	09.02.2017	वित्तीय शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में	पिछली बैठक के दौरान इस मुद्दे पर RBI के सहायक महाप्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि CBSE, RBI, SEBI, IRDA एवं PFRDA के द्वारा वित्तीय शिक्षण पर तैयार किए गए वर्कबुक को राज्य के स्कूलों में नियमित पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल कराया जाना है, जिसपर सरकार की ओर से इसे राज्य में जल्द लागू कराये जाने का आश्वासन दिया गया था नवीनतम सूचना अप्राप्त

बैंक से संबंधित मामले Issues Pertaining To Banks

बैंकों से संबंधित मामलों को पिछली SLBC की बैठक से SLBC द्वारा ATR के रूप में discuss किये जाने का प्रावधान किया गया है | पिछली SLBC की 62 वीं बैठक के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा की गई थी, उन मुद्दों को सभी संबंधित बैंको एवं LDMs को उनके द्वारा उचित कार्यवाही करने के लिए ATR के format में भेजा गया था, जिसका जबाब सभी LDMs एवं बैंको द्वारा प्रेषित किया गया है | इससे संबंधित compiled रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है | इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के पूर्व उन बैंको का उल्लेख जरूरी है जिन्होंने बार-बार लिखित एवं मौखिक आग्रह के बावजूद SLBC को ATR प्रेषित नहीं किया है | ये बैंक हैं- Bandhan Bank, Central Bank of India, Federal Bank, IDBI Bank, Indus Ind Bank, J & K Bank, Karur Vaisya Bank, Kotak Mahindra Bank, Laxmi Vilas Bank, South Indian Bank, Syndicate Bank और Yes Bank.

विस्तृत रिपोर्ट पृष्ठ सं-2 (a) से 2 (e) पर संलग्न है |

कार्यसूची सं.	3
बैठक दिनांक	15.05.2018
बैठक सं.	63

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के महत्वपूर्ण संकेतक (KEY INDICATORS)

(Rs in crores)

Sl. No	KEY INDICATORS	31.03.2017	31.12.2017	31.03.2018	Bench Mark
1	Deposit	186177.79	192003.77	198114.26	
2	Credit	81039.94	84018.21	85518.63	
3	Credit as per place of utilization* & RIDF**	26141.95	32955.98	33957.45	
4	Total Credit	107181.89	116974.19	119476.08	
5	CD Ratio	57.57	60.92	60.31	60
6	Priority Sector Advances (PSA)	43650.55	46176.52	46528.36	
7	Share of PSA to Total Advances (%)	53.86%	54.96%	54.40%	40
8	Agricultural Advances	13704.11	13249.68	13485.92	
9	Share of Agricultural Advances to Total Advances (%)	16.91%	15.77%	15.77%	18
10	i. Micro & Small Enterprises Advance	19753.78	21748.70	21711.74	
	ii. Share of Micro & Small Enterprises to Total Advances (%)	24.37%	25.88%	25.38%	
	iii. Share of Micro Enterprises in MSE	55.69%	58.44%	58.34%	
11	Advances to Weaker Sections	15268.40	14699.00	14852.75	
12	Share of Weaker Section Advances to Total Advances (%)	18.84%	17.50%	17.37%	10
13	DRI Advances	51.15	40.96	42.19	
14	Share of DRI Advances to Total Advances of last March (%)	0.07%	0.05%	0.05%	1
15	Advances to Women	11706.69	10993.94	11269.86	
16	Share of advances to women in Total advances (ANBC) (%)	14.45%	13.09%	13.18%	5
17	Advances to Minorities (Amount)	5679.66	5435.11	5620.21	
18	Share of Advances to Minorities under PSA (%)	13.01%	11.77%	12.08%	15
19	Gross N.P.A	4523.09	4992.87	5223.27	
	Provision	1797.99	2377.64	2790.54	
	Net NPA	2725.10	2615.23	2432.73	
	Gross NPA Percentage	5.58%	5.94%	6.10%	
	Net NPA Percentage	3.36%	3.11%	2.84%	
20	Branch Net-Work (in no.)-Rural	1513	1496	1497	
	Semi-Urban	778	783	785	
	Urban	704	721	726	
	Total	2995	3000	3008	
21	ATM installed in Jharkhand	3469	3536	3557	

*Annexure- V,

पर्यवेक्षण

जमा वृद्धि (Deposit Growth)

झारखंड राज्य में बैंकों की सकल जमा में पिछले एक साल में, यानि 31 मार्च, 2017 से 31 मार्च 2018 तक रूपये 11936.47 करोड़ की वर्ष-वार वृद्धि हुई है | वर्ष-दर-वर्ष सकल जमा में 6.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है |

ऋण वृद्धि (Credit Growth)

राज्य में बैंकों के कुल क्रेडिट में पिछले एक साल में रूपये 4478.69 करोड़ की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई | वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की दर 5.52 प्रतिशत दर्ज की गई है |

क्रेडिट - जमा अनुपात (C.D Ratio)

कई तिमाहियों में CD ratio में लगातार दर्ज की गई गिरावट के बाद पिछली तिमाही में बैंकों का सीडी अनुपात बढ़कर 60.92% हो गया था जो पुनः आंशिक रूप से कम होकर मार्च 2018 में 60.31 % रह गया है, जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 60% से कुछ अधिक है | यद्यपि इस दिशा में बैंको का प्रयास सराहनीय कहा जा सकता है , परंतु सितम्बर 2016 में 61.16% की CD ratio की तुलना में यह अभी भी कम है एवं सभी बैंकों को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है |

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (PSA)

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 6.60% की वृद्धि दर्ज की गयी है। वर्तमान में समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम कुल अग्रिम का 54.40 % है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 40 प्रतिशत से ज्यादा है।

कृषि अग्रिम (Agriculture Credit)

31 मार्च 2018 को कृषि अग्रिम रु. 13485.92 करोड़ है जो कुल अग्रिम का 15.77 प्रतिशत है। पिछले वर्ष में कृषि ऋण कुल अग्रिम का 16.91 % था | यद्यपि पिछले एक साल में रु. 3757.56 करोड़ कृषि ऋण के अंतर्गत संवितरित किये गए हैं, परंतु वर्तमान में कृषि क्षेत्र का कुल अग्रिम मार्च 2017 की तुलना में लगभग रु 218.19 करोड़ कम है, जो की एक चिंतनीय प्रश्न है और बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में अपेक्षित ऋण प्रवाह नहीं किये जाने की ओर स्पष्ट संकेत करता है | लगभग प्रत्येक SLBC की त्रैमासिक बैठक में इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की जाती रही है परंतु अब यह लाजिमी ही गया है कि सभी बैंको को विशेष कार्ययोजना बनाकर कृषि ऋण में वृद्धि करने के लिए अथक प्रयास करना पड़ेगा |

कमजोर वर्ग (Weaker Section)

31 मार्च 2018 तक झारखण्ड राज्य में कमजोर वर्ग को रूपये 14852.75 करोड़ (17.37 प्रतिशत) का ऋण दिया गया है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 10 प्रतिशत से बेहतर है।

महिलाओं को ऋण (Advance to Women)

31 मार्च 2018 तक महिलाओं को दिये गए ऋण का कुल शेष (O/S) रु. 11269.86 करोड़ है, जो की कुल अग्रिम का लगभग 13.18 % है | यह राष्ट्रीय बेंचमार्क 5% से ऊपर है |

अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण (Advance to Minority Community)

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण रूपये 5620.21 करोड़ है | यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का 12.06 % है, जो मानक 15 प्रतिशत से कम है | इसमें अपेक्षित सुधार लाने के लिए सभी बैंकों को ध्यान देने की आवश्यकता है |

31 मार्च 2018 को राज्य का ऋण-जमा अनुपात

भारतीय रिजर्व बैंक के MASTER CIRCULAR. No – RPCD.CO.LBS.BC.No. 9/02.01.001/2014-15, दिनांक 01.07.14 के अनुसार बैंकों का ऋण जमा अनुपात का मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर होने वाले उपयोग और आर आई डी एफ के अनुसार किया जाना है।

तदनुसार, झारखण्ड राज्य का ऋण -जमा अनुपात निम्नवत है :-

(Rs in crore)

DETAILS		31st March, 2017	31st March, 2018	
Aggregate Deposits		186177.79	198114.26	
CORE ADVANCES	81039.94		85518.63	
As per place of Utilization	21861.39		29066.92	
RIDF	4280.57		4890.53	
NET ADVANCES	107181.89		119476.08	
ऋण-जमा अनुपात		57.57		60.31

(परिशिष्ट-4, परिशिष्ट - 5)

नोट : कृपया ऋण - जमा अनुपात का विस्तृत विश्लेषण हेतु संलग्नक का संदर्भ लें जिसमें विभिन्न पैरामीटर ग्रामीण/अर्द्धशहरी/शहरी केन्द्र, बैंकवार और जिलावार समीक्षा आदि से संबंधित पूर्ण विवरण संलग्न है।

कार्यसूची सं.	4
बैठक का दिनांक	15.05.2018
बैठक संख्या	63

**4.1 वार्षिक ऋण योजना 2017-18 के तहत
उपलब्धियों की समीक्षा : 31 मार्च 2018 तक**

समग्र स्थिति

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार वार्षिक ऋण योजना 2017-18 के क्रियान्वयन में बैंकों का पिछले वर्ष की तुलना में सेक्टर वार उपलब्धि:

(रु करोड़ में)

SECTOR	ANNUAL TARGET (2016-17)	ACHIEVEMENT IN AFY 2016-17		ANNUAL TARGET (2017-18)	ACHIEVEMENT IN AFY 2017-18	
	AMT	AMT.	%	AMT.	AMT	%
1	2	3	4	5	6	7
Agriculture	7356.42	3032.59	41.22	7682.37	3757.56	48.91
MSME	6526.97	7420.13	113.68	7329.51	10337.95	141.05
OPS	3361.72	1929.23	57.38	3821.41	2132.47	55.80
Total Priority	17245.11	12381.95	71.80	18833.29	16227.98	86.16
Non Priority	10361.68	9525.43	91.92	8582.15	8605.03	100.26
Total	27606.79	21907.38	79.35	27415.45	24833.01	90.58

टिप्पणियां :

- ✚ वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 90.58 % समग्र ऋण का संवितरण हुआ है। यद्यपि यह उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष में हुई 79.35% की अपेक्षाकृत बेहतर है, परंतु सभी बैंकों के द्वारा वार्षिक ऋण योजना की शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए।
- ✚ कृषि क्षेत्र में, वार्षिक ऋण योजना 2017-18 के अंतर्गत पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान 3757.56 करोड़ रुपये का शुद्ध संवितरण हुआ है, जो कि पिछले वित्त-वर्ष की पूरी अवधि के दौरान किये गए संवितरण से रु. 724.97 करोड़ अधिक है। कृषि क्षेत्र में कुल वार्षिक योजना के

विरुद्ध केवल 48.91% ऋण का संवितरण ही हो पाया है | कृषि क्षेत्र का मार्च 2018 में कुल o/s मार्च 2017 से भी कम है, जिसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र में ऋण संवितरण की स्थिति में और अधिक सुधार की आवश्यकता है | सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है की वे नाबार्ड के तत्वाधान में हुए SLBC-agriculture sub-committee की बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों जैसे कि-कम से कम 30% कृषि ऋण का सवितरण मियादी ऋण के रूप में सुनिश्चित करना, दुग्ध उत्पादन , मतस्य पालन, मुर्गी पालन एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों के लिए ऋण देना इत्यादि को अपनी शाखाओं के माध्यम से पूरी दृढ़ता के साथ लागू कराने का प्रयास करें ताकि कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढ़ाया जा सके |

- ✚ MSME sector में बैंक की उपलब्धि को देखते हुए पहले भी यह चर्चा की गई है कि जिलों एवं बैंको के प्रदर्शन के आधार पर LDMS को ACP बनाते समय इन बातों को पूरी तरह ध्यान में रखा जाना चाहिए और MSME sector में ACP target में तर्कसंगत वृद्धि की जानी चाहिए | इस वित्तीय वर्ष में MSME के वार्षिक बजट में लगभग 17% की वृद्धि प्रस्तावित की गई है |
- ✚ कृषि ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कुल अग्रिम एवं CD ratio में विभिन्न जिलों एवं बैंको द्वारा प्राप्त किये गए उपलब्धि प्रतिशत को पृष्ठ सं-7(a) एवं 7(b) में दर्शाया गया है |
- ✚ 2017-18 के लिए दिये गए ACP के विरुद्ध बैंकवार एवं जिलावार हुई उपलब्धि को annexure-6 में दर्शाया गया है |
- ✚ Agriculture Term Loan में बैंकवार एवं जिलावार segment wise संवितरण और o/s का रिपोर्ट annexure-7 में दिया गया है |

ANNUAL CREDIT PLAN 2018-19

- राज्य के सभी अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालयों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित "Potential Linked Plan" के व्यापक रूपरेखा के आधार पर "वार्षिक ऋण योजना" तैयार की गई ।
- अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालयों के द्वारा तैयार इन "वार्षिक ऋण योजनाओं" को सभी जिलों के DLCC की बैठक में प्रस्तुत किया गया एवं DLCC के द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत वार्षिक ऋण योजनाओं को जिला स्तर पर अपनाया एवं लागू किया जा रहा है ।
- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) के द्वारा सभी जिलों से प्राप्त "वार्षिक ऋण योजनाओं" को संकलित कर राज्य की "वार्षिक ऋण योजना" बनाई गयी है जिसे सभी बैंकों एवं LDMs को उपलब्ध करा दिया गया है ।
- सभी जिलों से प्राप्त वार्षिक ऋण योजनाओं के आधार पर राज्य के सभी बैंक एवं जिलों का "वार्षिक ऋण योजना" पृष्ठ संख्या- 8(a)-8(g) संलग्न है ।
- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृषि उप-समिति के निर्णयानुसार "वार्षिक ऋण योजना" में कृषि के sub-sector का जिलावार लक्ष्य संलग्न है ।

(Amt. in Crores)

PRIORITY SECTOR ADVANCES							
(Disbursement Budget)							
Agriculture			MSME				Education (priority)
Crop Loan	Agri.Term Loan	Total	MICRO	SMALL	MEDIUM	TOTAL	
4937.04	3399.56	8336.60	5043.98	2364.85	1151.52	8560.35	1086.50
Housing	OPS	Total Priority Sector					21110.55
2145.52	981.58						
NON-PRIORITY SECTOR ADVANCES							
(Disbursement Budget)							
Heavy Industries	Education	Housing	Others	Total Non-Priority Sector			
562.60	522.09	953.61	6735.04	8773.34			
TOTAL ADVANCES (Disbursement Budget)						29883.89	

कार्यसूची सं.	5
बैठक का दिनांक	15.05.2018
बैठक संख्या	63

5. REVIEW OF LENDING ऋण की समीक्षा

5.1. कृषि एवं किसान क्रेडिट कार्ड

राज्य में सभी बैंकों का कुल कृषि साख रु. 13485.92 करोड़ है जो सकल ऋण का 15.77 % है। यह राष्ट्रीय मानक 18 प्रतिशत से कम है। बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों, नाबार्ड एवं अन्य संबंधित हितधारकों के सामूहिक प्रयास से इसे पुनः बैंचमार्क 18% से ज्यादा किये जाने का यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए ।

झारखण्ड में के सी सी की स्थिति (STATUS OF KCC IN JHARKHAND)

(Amt. In Crores)

Type Of Banks	Disbursement During 2017-18		Outstanding In KCC Accounts As of 31.03.2018	
	A/C	Amt.	A/C	Amt.
Public Sector Banks	515214	1981.99	1241793	4905.20
Pvt. Banks	34814	180.22	29027	166.55
Total	550028	2162.21	1270820	5071.75
RRB	302774	1068.47	366726	1389.47
Co-op Banks	2237	6.40	19343	32.21
Total	855039	3237.08	1656889	6493.43

(KCC से संबंधित प्रतिवेदन annexure-8 में उल्लिखित है)

- ❖ सभी सामान्य के सी सी खातों को Smart K.C.C खातों में परिवर्तित कर उन खातों में आवश्यक तौर पर Rupay Card जारी कर देना था, ताकि यह ATM एवं POS में भी कार्य कर सके । दिनांक 31.03.2018 तक बैंकों द्वारा दिये गए आंकड़े के अनुसार कुल 1484043 eligible KCC खातों में से 1286611 खातों में रूपे कार्ड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है जिसके विरुद्ध 1263900 खातों में (98.23%) rupay debit card निर्गत किये गए हैं।

(विवरण पृष्ठ सं-9(a) एवं 9(b) में संलग्न है)

5.2. (क) सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों का वित्त पोषण

5.2.1. सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों का वित्त पोषण (एम एस एम ई) (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र) (Accounts in thousands) (Amt. in crore)

Sl. No.	Particular		Outstanding position as at the end of		
			March 2017	March 2018	
(1)	(2)		(3)	(4)	
MICRO & SMALL ENTERPRISES					
1	Micro Enterprises	Accounts	447	544	
		Amount	11001.52	12667.89	
2	Small Enterprises	Accounts	96	45	
		Amount	8752.27	9043.85	
3	Total Micro and Small Enterprises (MSE sector)	Accounts	543	566	
		Amount	19753.79	21711.74	
MEDIUM ENTERPRISES					
4.	Total of Medium Enterprises	Accounts	31	09	
		Amount	1967.43	1857.59	
MSME					
TOTAL MSME (PRIORITY SECTOR ADVANCES)		Accounts	574	597	
		Amount	21721.22	23569.33	
5.	a.	Share of Credit to Micro Enterprises in total credit to MSE sector	Percent share of amounts (stipulation: 60%)	55.69%	58.34%
	b.	Share of credit to MSE sector in NBC/ ANBC	Percent share of amount	24.37%	25.38%

(MSME रिपोर्ट -annexure-9)

COVERAGE UNDER CGTMSE (for eligible Loans Upto Rs. 2.00 Crore in MSE) (Position as on 31.03.2018)

(A/C in 000, Amt.in Cr.)

Eligible MSE loan up to Rs. 2.00 Crore		Coverage under CGTMSE	
TOTAL		TOTAL	
A/C	Amt	A/C	Amt.
364	16683.31	119	4349.78

(रिपोर्ट पृष्ठ सं- 10 में सलग्न है)

टिप्पणियां

- ✚ झारखंड में कुल एमएसई में माइक्रो सेक्टर क्रेडिट की हिस्सेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार 60% की बेंच मार्क के विरुद्ध मार्च, 2018 में 58.34 % है।
- ✚ बैंको द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार , झारखण्ड राज्य में, रु. 2 करोड़ की सीमा के अंदर कुल 3.64 लाख (लगभग) MSE ऋण खातों हैं, जो cgtmse coverage के लिए eligible हैं, परंतु इनमें से केवल 1.19 लाख (लगभग) ऋण खातों में, यानी कि सिर्फ 32.69 % खातों में ही CGTMSE कवरेज लिया गया है |
- ✚ कमोबेश सभी बैंकों का CGTMSE कवरेज प्रतिशत काफी कम है परंतु खास कर कुछ निजी बैंकों का CGTMSE कवरेज का प्रतिशत बिलकुल नगण्य है | अतः इन बैंकों एवं अन्य सभी दूसरे बैंकों से यह आग्रह है कि वे अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा खातों में CGTMSE कवरेज लेने का प्रयास करें |

5.2 (ख) “प्रधानमंत्री मुद्रा योजना”

दिनांक 8 अप्रैल, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई | यह योजना मुख्यतः गैर-कृषि क्षेत्र के छोटे उद्यमियों को बैंक द्वारा वित्त पोषण के लक्ष्य से शुरू की गई थी | परंतु वर्तमान में DFS, Ministry of Finance, GOI के पत्रांक - 29/2/2016-IF-2 दिनांक 23.06.2016 के द्वारा कृषि क्षेत्र के Allied Activities -e.g. Pisciculture, beekeeping, poultry, diary, fishery, agriclinics & agribusiness centres, food & agro processing एवं इन गतिविधियों को सहारा देने वाली वैसी सेवाएँ जो जीविकोपार्जन अथवा आय अर्जन को promote करती हैं, इत्यादि को भी 01.04.2016 से PMMY के तहत शामिल कर लिया गया है | PMMY योजना के तहत दिये जाने वाले सभी ऋणों का NCGTC (National Credit Guarantee Trustee Co Ltd) द्वारा guarantee cover (CGFMU-Credit Guarantee for Mudra Unit) सुनिश्चित किया गया है |

इस योजना की राज्य में प्राप्त उपलब्धि निम्नलिखित है:

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में झारखण्ड की उपलब्धि (01.04.17 से 31.03.18 तक)

(राशि करोड़ में)

	शिशु		किशोर		तरुण		TOTAL	
	NO	AMT	NO	AMT.	NO	AMT.	NO	AMT.
Sanctioned	238790	748.31	70857	1401.85	11347	903.85	320994	3054.02
Disbursed	238313	737.69	71843	1333.02	11302	861.52	321458	2932.24

MUDRA पोर्टल पर दिये गए आंकड़ों के अनुसार राज्य में Micro Finance Agencies द्वारा लगभग 1118607 खातों में रु 2582.15 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है और 1118607 खातों में रु 2498.51 करोड़ की राशि वितरित की गई है | इस तरह MUDRA योजना के तहत राज्य में अब तक कुल 1440065 खातों में रु 5430.75 करोड़ की राशि का संवितरण हुआ है |

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-12 (a) एवं 12 (b) में सलग्न है)

5.2 (ग) स्टैंड अप इंडिया ऋण योजना

स्टैंड अप इंडिया ऋण योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य की उपलब्धि 30.04.2018 तक SIDBI के पोर्टल के आधार पर इस प्रकार है-

Total Beneficiaries	Women Beneficiaries	SC/ST Beneficiaries	Loan Disbursed Amt (Rs in Cr)
571	503	68	53.19

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-12(c) एवं 12 (d) में सलग्न है)

5.3. शिक्षा ऋण Education loan

शिक्षा ऋण योजना के तहत बैंको का निष्पादन

(Amt. in crore)

Particulars	As on 31.03.17	As on 31.03.18				Total As on 31.03.18	GROWTH Y-O-Y IN EDU. LOAN	DISBURSE MENT MADE DURING AFY 2017- 18
		Public Sector Bank	Private Sector Bank	RRB	Coop. Bank			
No. of Accounts	64273	60757	551	855	3	62166	324.10	11624
Amount (In crore)	2554.26	2833.30	18.78	26.13	0.14	2878.36		418.30

(Annexure-10)

- पिछली SLBC के दौरान वर्तमान वित्तीय वर्ष के दिसम्बर तिमाही तक शिक्षा ऋण के तहत कुल 12133 खातों में 467.33 करोड़ रु की राशि के संवितरण की रिपोर्टिंग की गई थी | इसके विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि Uco Bank, बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र , Central Bank of India एवं OBC द्वारा पिछले तिमाही तक दर्शाये गए disbursement से कम की रिपोर्टिंग की गई है | इन बैंको के अधिकारियों द्वारा यह सपष्टीकरण दिया गया कि पिछली बार यह रिपोर्टिंग गलत थी |
- RBI के प्रावधानों के तहत रु. 4.00 लाख तक के शिक्षा-ऋण में किसी भी तरह के SECURITY की आवश्यकता नहीं है, एवं रु.7.50 लाख तक के बिना SECURITY या GUARANTEE पर दिया गया शिक्षा ऋण पर CREDIT GUARANTEE उपलब्ध है, इसीलिये रु 7.50 लाख तक के शिक्षा-ऋण C.N.T या S.P.T एक्ट के प्रभाव से मुक्त माना जा सकता है | इसे ध्यान में रखते हुए 54 वीं SLBC बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि SC/ST संवर्ग के योग्य छात्रों को रु.7.50 लाख तक के शिक्षा ऋण देने के लिए बैंकों के द्वारा विशेष अभियान चलाया जाय |
- इस वित्तीय वर्ष के दौरान कुल संवितरित ऋण में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को रु.7.50 लाख तक दिये गए शिक्षा ऋण की स्थिति इस प्रकार है:

	स्वीकृत		वितरित	
	संख्या	राशि (रु करोड़ में)	संख्या	राशि (रु करोड़ में)
कुल दिया गया शिक्षा ऋण (2017-18)			11624	418.30
रु 7.50 लाख तक दिया गया कुल शिक्षा ऋण	4264	189.37	4032	90.23
अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को दिया गया रु 7.50 लाख तक दिया गया शिक्षा ऋण	943	38.52	924	19.63

(रिपोर्ट संख्या -10 A)

5.4- आवास ऋण

Performance of Banks under Housing loan Scheme

(आवास ऋण योजना के तहत बैंकों का प्रदर्शन)

(रु .करोड़ में)

Particulars	Up to 31.03.17	31.03.2018				Total Up to 31.03.18	GROWTH Y-O-Y IN HOUS. LOAN	Disbursements made in AFY 17-18
		Public Sector Banks	Private Sector Banks	RRB	Coop. Banks			
खाता की सं.	79460	69356	5606	962	48	75972	1489.78	13930
राशि	6563.86	7373.10	635.00	41.87	3.67	8053.64		2167.11

(रिपोर्ट -annexure-11)

5.5 CREDIT FLOW TO SPECIAL CATEGORY OF BORROWERS (ऋण लेने वालों की विशेष श्रेणी हेतु ऋण प्रवाह)

5.5.1 अल्पसंख्यक समुदायों हेतु ऋण प्रवाह

31 मार्च, 2018 की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है

(रु .करोड़ में)

31 मार्च, 2017		% Share	31 मार्च, 2018		% Share
Total P.S.A	Loans to Minority Community		Total P.S.A	Loans to Minority Community	
43650.55	5679.66	13.01%	46528.36	5620.21	12.08%

(रिपोर्ट -annexure-13)

5.5.2 महिलाओं के लिए ऋण प्रवाह

31 मार्च, 2018 की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है

(रु .करोड़ में)

31 मार्च, 2017		PERCENTAGE OF CREDIT TO WOMEN	31 मार्च, 2018		PERCENTAGE OF CREDIT TO WOMEN
Gross Credit	Of which to Women		Gross Credit	Of which to Women	
81039.94	11706.69	14.45%	85518.63	11269.86	13.18%

(रिपोर्ट -annexure-13)

5.5.3 डीआरआई के लिए ऋण प्रवाह(DRI)

31 मार्च, 2018 को इस क्षेत्र में बैंकों के प्रदर्शन, नीचे इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

31 मार्च, 2017		DRI Percentage in Net Credit	31 मार्च, 2018		DRI Percentage in Net Credit
Net Credit	DRI		Net Credit	DRI	
81039.94	51.15	0.07%	85518.63	42.19	0.05%

(रिपोर्ट -annexure-12)

5.5.4. SC/ST के लिए ऋण प्रवाह

31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लिए ऋण प्रवाह की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है- :

(रु करोड़ में.)

31 मार्च, 2017		Percentage	31 मार्च, 2018		Percentage
Net Credit	Loans to SC/ST		Net Credit	Loans to SC/ST	
81039.94	13579.96	16.75%	85518.63	12968.55	15.16%

(रिपोर्ट -annexure-13)

5.6. Scheme for financing of Women SHG

एसएचजी महिलाओं के वित्तपोषण हेतु योजना

बैंकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में पूरे राज्य में 164470 SHGs के S/B खाते हैं , जिनमें से 115232 खातों का credit linkage है, जिसमें कुल रु 924.04 करोड़ स्वीकृत किया गया है और वर्तमान में O/S राशि रु 588.25 करोड़ है |

(रिपोर्ट- Annexure-15)

5.7. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

एन आर एल एम की उपलब्धि (31 मार्च, 2018 तक) Source-JSLPS

संकेतक Indicators	Status as on March'17	Addition during AFY-17-18	Cumulative status as on date since Inception
No of Blocks	125	75	200
No of Villages	7038	8695	15733
Total No of SHGs supported by SRLM	80789	51742	132531
Total families supported by SRLM	979644	618261	1597905
No of SHG receiving R.F	37299	18442	55741
Amt. of RF disbursed (Rs in Lacs)	5566	2795	8361
No of SHG receiving CIF	27349	6552	33901
Amt of CIF disbursed (Rs in Lacs)	15706	3278	18984
No. of SHG credit linked with Banks	20321	46264	66495
Amt of credit availed from Banks (Rs in lacs)	10165	38840.45	49005.45

- वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंको द्वारा SLBC के पोर्टल पर प्रदत्त जानकारी के अनुसार कुल 40987 SHGs को credit लिंक किया गया है, जबकि JSLPS के द्वारा इस अवधि में credit linked किये गए SHGs की संख्या 46264 बताई गई है | JSLPS से अनुरोध है कि वे बैंको से अद्यतन जानकारी लेकर अपनी रिपोर्टिंग में आवश्यक सुधार कर सही आंकड़े SLBC को प्रेषित करें |

(JSLPS से प्राप्त SHG का बैंकवार एवं जिलावार प्रगति प्रतिवेदन पृष्ठ संख्या-16 (a) एवं 16 (b) में दिया गया है |)

कार्यसूची सं.	6
बैठक की तिथि	15.05.2018
बैठक की संख्या	63

**वित्तीय समावेशन एवं
प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)**

झारखंड में प्रधानमंत्री जन धन योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

A. BC (बैंक मित्र) द्वारा SSA के कवरेज की स्थिति

SSA की कुल संख्या	BC द्वारा SSA का coverage (Fixed Location)	बैंक शाखा द्वारा SSA का coverage	uncovered	No of Micro ATMs enabled & allotted to BCs	No of Pin Pads enabled & allotted to BCs
4178	3701	477	Nil	3587	5130

{रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या -17 (a) & 17 (b)}

B Online transaction करने वाले BC की स्थिति

बैंको द्वारा नियुक्त किये गए BC की कुल संख्या	Online transaction करने वाले BC की कुल संख्या	50 से कम प्रतिदिन transaction करने वाले BC की कुल संख्या	50 से 100 transaction प्रतिदिन करने वाले BC की कुल संख्या	100 से ज्यादा transaction प्रतिदिन करने वाले BC की कुल संख्या
5799	4963	3601	893	469

{रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या -17 (c)}

C. PMJDY के तहत 31.12.2017 तक खोले गए BSBD (Basic Savings Bank Deposit) खातों की स्थिति

31.12.2017 तक खोले गए बीएसबीडी खातों की संख्या			PMJDY खातों में जारी किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या	आधार Seeding किये गये PMJDY खातों की संख्या	मोबाइल Seeding किये गये PMJDY खातों की संख्या	बैंकों द्वारा वितरित किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या	बैंकों द्वारा activate किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या
ग्रामीण	शहरी	कुल					
A	B	C	D	E	F	G	H
8049760	3152433	11202193	8145690	10049845	7433880	6888941	5375740

{रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या -17 (d) & 17 (e)}

NB: (Coloumn A, B, C, D एवं E की जानकारी DFS portal से ली गई है जबकि Coloumn F, G एवं H में दी गई जानकारी बैंकों द्वारा दी गई है)

यद्यपि पीएमजेडीवाइ योजना के तहत खोले गए खातों में अब तक कुल 8145690 रुपये कार्ड जारी किए गए हैं , परन्तु प्राप्त सुचना के आधार पर यह पता चल रहा है कि जारी किये गए रुपये कार्ड में से केवल 6888941 कार्ड ही अब तक वितरित किये गए हैं और उनमे से भी अब तक केवल 5375740 खातों में रुपये कार्ड activate हो पाया है | बैंकों/LDMS से आग्रह है कि वर्तमान समय में Cashless transaction को बढ़ावा देने के लिए शत प्रतिशत रुपये कार्ड का activation करना अत्यंत जरूरी है , और BCs द्वारा किये जाने वाले प्रतिदिन transaction की संख्या को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किये जाने की आवश्यकता है |

राज्य में PMJDY खातों में दिये गए ओवरड्राफ्ट facility एवं death claim settlement से संबंधित बैंकों से प्राप्त आंकडा पृष्ठ संख्या-18 (a) में दर्शाया गया है |

**प्रधानमंत्री जन-धन योजना” के द्वितीय चरण में, जन सुरक्षा हेतु,
लागु किये गये, विभिन्न बीमा एवं पेन्शन योजनाएं :**

दिनांक: 31.03.2018 तक इन योजनाओं में सभी बैंकों की उपलब्धि निम्नवर्णित है-

PMJJBY		PMSBY		APY		
Total Enrolment	Premium Received (Rs. in Cr)	Total Enrolments	Premium Received (Rs. in Cr)	Target for FY 2017-18	Total Enrolments during 17-18	% achievement during FY 17-18
540461	17.83	2706526	2.97	195290	118298	60.57 %

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-18 (b) सलंग्न है)

**वित्तीय समावेशन एवं BRANCH EXPANSION पर भारतीय रिज़र्व बैंक का
अद्यतन दिशानिर्देश एवं 5000 से ऊपर के गाँवों में बैंकिंग शाखा खोलने संबंधित रोडमैप**

भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व के निर्देशानुसार 5000 से ज्यादा आबादी वाले सभी गाँवों में दिनांक 31.03.17 तक बैंक की शाखा खोलना अनिवार्य किया गया था | झारखण्ड राज्य में ऐसे 259 गाँवों को चिन्हित किया गया था एवं पाया गया था कि इनमें से 122 गाँवों में ही बैंक की शाखा मौजूद है , बाकी के 137 गाँवों को विभिन्न बैंकों को आवंटित कर उन्हें brick & mortar branch खोलने के लिए सूचित किया गया था |

आरबीआई के नये दिशा निर्देश के अनुसार सप्ताह में कम से कम पांच दिन, प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे एक नियत स्थल पर कार्य कर रहे BC को 'बैंकिंग आउटलेट', माना जा सकता है | पिछली SLBC की बैठक तक इस निर्देश के अनुसार निर्धारित 137 में 136 गाँव में बैंक की शाखा या FIXED LOCATION BC खुल चुके थे। Vijaya Bank के प्रतिनिधि द्वारा पिछली SLBC की बैठक में एक सप्ताह के अंदर रांची जिले के Chanho Block के Patrattu गाँव में BC नियुक्त किये जाने का आश्वासन दिया गया था | कुछ समय पश्चात Vijaya Bank के द्वारा मौखिक रूप से SLBC को BC नियुक्त कर लिए जाने की बात बताई गई थी परंतु उनसे बार बार आग्रह के पश्चात भी अभी तक BC का details SLBC को उपलब्ध नहीं कराया गया है | SLBC को प्रेषित ATR में Vijaya Bank द्वारा पुनः नयी जानकारी दी गई है जिसमें उन्होंने उक्त गाँव में BC की नियुक्ति ना कर नै शाखा खोलने की बात की है जिसपर उनके द्वारा प्रधान कार्यालय से पत्राचार किया जा रहा है |

पिछली बार की रिपोर्टिंग से इतर कुछ बैंको द्वारा इस बार कुछ स्थानों पर BC के कार्यरत नहीं होने की जानकारी दी गई है | SLBC एवं RBI द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी मांगे जाने के बावजूद इन बैंको द्वारा कोई भी संतोषप्रद जबाब नहीं दिया जा रहा है |

बैंको द्वारा प्राप्त अद्यतन स्थिति के अनुसार देना बैंक ने 04, United Bank of India ने 07, Uco Bank ने 02, Vijaya Bank ने 01 एवं Indian Bank ने 01 यानि कुल 16 स्थानों पर fixed location BC नहीं होने की रिपोर्टिंग की है |

(संबंधित रिपोर्ट पृष्ठ सं- 19 a पर संलग्न है)

कार्यसूची सं	7
बैठक का दिनांक	15.05.2018
बैठक सं	63

एन पी ए & वसूली - एन पी ए/ बैंकों के स्ट्रेस्ड आस्तियों के रुकाव हेतु नियंत्रक उपाय एवं वसूली से संबंधित उपाय

गैर निष्पादनीय आस्तियां

राज्य के बैंकों में दी 31 मार्च 2018 को एन पी ए की स्थिति निम्नवत है -:

[राशि करोड़ में]

विवरण	31.03.17	31.12.17	31.03.18	Variation over last FY	% Variation (over last FY)
Advances	81039.94	84018.21	85518.63	4478.69	3.67%
Gross NPA	4523.09	4992.87	5223.27	700.18	10.38%
Provision	1797.99	2377.64	2790.54	992.55	32.23%
Net N.P.A	2725.10	2615.23	2432.73	(-)292.37	
Percentage of Gross NPA	5.58 %	5.94%	6.10%		0.52%
percentage of Net NPA	3.36 %	3.11%	2.84 %		(-)0.52%

(रिपोर्ट- annexure-19)

झारखंड राज्य में बैंकों की गैर निष्पादनीय आस्तियां (N.P.A), एक चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुकी है। रु 5223.27 करोड़ का gross NPA, जो सकल अग्रिम का 6.10 % है, एक चिंताजनक आंकड़ा है।

विभिन्न segment में राज्य में मांग और वसूली से संबंधित आंकड़े annexure-17 एवं 18 में सलगनक के रूप में दर्शाये गए हैं।

सर्टिफिकेट केस का स्थिति

दिनांक 31 मार्च 2018 को राज्य के बैंकों में सर्टिफिकेट केस के लंबित मामलों की स्थिति इस प्रकार है:

[राशि करोड़ में]

Cases pending upto last quarter		Cases Filed during last Qtr.		Cases dispoed during last Qtr.		status as on 31.03.2018	
सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	संख्या	राशि
110318	360.69	39311	33.61	37438	229.02	112191	165.28

(रिपोर्ट- annexure-20)

DRT केस की स्थिति

दिनांक 31 मार्च 2018 तक बैंकों के डी आर टी केसों की स्थिति इस प्रकार है :-

[राशि करोड़ में]

Cases pending as of last quarter		Cases Filed during last Quarter		Cases Resolved during last Quarter		Status as of 31.03.18	
सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि
2067	749.48	370	25.62	542	30.74	1895	744.37

(रिपोर्ट- annexure-21)

SARFAESI केस की स्थिति

दिनांक 31 मार्च, 2018 तक SARFAESI cases की position निम्नवत है:

(Rs in Cr)

Notices Issued U/S 13 (2) of SARFAESI Act		Out of which symbolic possession taken under 13(4)		Request sent to Dist Authority for assistance in Physical Possession		Physical Possession taken		No. of cases pending at dist. level
A/C	Amt	A/C	Amt	A/C	Amt	A/C	Amt	A/C
5902	1624.98	2418	725.83	621	433.44	135	313.95	486

विभिन्न बैंको से प्राप्त Physical possession के लिए जिले के संबंधित अधिकारियों के पास भेजे गए cases का जिलावार ब्यौरा रिपोर्ट संख्या -21 (a) में दर्शाया गया है ।

कार्यसूची सं	8
बैठक का दिनांक	15.05.2018
बैठक सं	63

सरकार प्रायोजित कार्यक्रम

8.1 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

पीएमईजीपी के तहत आवेदनों के ई-ट्रैकिंग के लिए प्रस्तावित सेवाएँ अधिकांश बैंकों के द्वारा अपने बेवसाइट पर समाविष्ट कर ली गई हैं। इस प्रक्रिया के लिए KVIC के द्वारा सभी बैंकों को उनके द्वारा system number उपलब्ध कराने के पश्चात् User ID और Password दिये जाने का प्रावधान किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंकों द्वारा PMEGP लोन की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ही की जा रही है। SLBC द्वारा PMEGP पोर्टल से ली गई जानकारी के अनुसार दिनांक 31.03.2018 तक की स्थिति इस प्रकार है-

(राशि करोड़ में)

Forwarded to Banks		Sanctioned by Banks		Rejected/ Returned for rectification		Pending	
NO	MM Involved	NO	MM Involved	NO	MM	NO	MM
10699	268.73	1731	39.90	7674	189.15	1346	36.18

(पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 31.03.2018 की स्थिति annexure-14 पर दर्शायी गई है)

8.2 NULM

शहरी विकास विभाग के पोर्टल से प्राप्त NULM से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन रिपोर्ट संख्या-22 (a) में 2 में दर्शायी गई है।

कार्यसूची संख्या	9
बैठक की तारीख	15.05.2018
बैठक संख्या	63

RSETI & FLCC का परिचालन

झारखंड राज्य में आरसेटी की वर्तमान स्थिति निम्नांकित है : (as of 31.03.2018)
झारखंड राज्य के 24 जिलों में निम्नलिखित सूची के अनुसार , विभिन्न बैंको के द्वारा 24 आरसेटी और 1 रुडसेटी संचालित किया जा रहा हैं |

बैंक ऑफ इंडिया	-	11 जिले
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	-	8 जिले
इलाहाबाद बैंक	-	3 जिले
पंजाब नेशनल बैंक	-	2 जिले
कुल		24 जिले
एवं रुडसेटी (रांची जिले की सिल्ली में केनरा एवं सिंडिकेट बैंक द्वारा संचालित)		1 जिला

AFY 17-18 का वार्षिक लक्ष्य :

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या -586 ; प्रशिक्षनार्थियों की संख्या - 17377
उपलब्धि: प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या -636 प्रशिक्षनार्थियों की संख्या - 17669
{State Director, RSETI से प्राप्त रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या-23 (a)}

RSETI भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति,

कार्य सम्पूर्ण/ नये भवन में RSETI का संचालन - 06
भवन निर्माण कार्य लगभग सम्पूर्ण/finishing work जारी - 03
भवन निर्माण कार्य प्रगति पर - 15
भवन निर्माण से संबंधित कोई भी कार्य प्रारंभ होना बाकी - 01
(सभी RSETI निदेशकों से प्राप्त विवरणी पृष्ठ सं-23 (b) से 23 (d) में संलग्न है)

RSETI प्रशिक्षार्थियों की बैंकों से वित्तीय संबन्धता (CREDIT LINKAGE) की स्थिति :

AFY 2016-17 के दौरान		AFY 2017-18 के दौरान	
कुल प्रशिक्षनार्थी	Credit Linked	कुल प्रशिक्षनार्थी	Credit Linked
19605	2855	17660	2461

(विभिन्न RSETIs से प्राप्त रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या-23 (e) एवं 23 (f) पर उपलब्ध है)

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (FLCCs) का संचालन

वर्तमान में 24 वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (FLCCs) झारखंड के राज्य में परिचालन कर रहे हैं :

बैंक का नाम	बैंक वित्तीय साक्षरता केन्द्र परिचालन (जिला स्तर पर)	संख्या
बीओआई	रांची, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम (पश्चिम), सिंहभूम (पूर्वी), गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, चतरा, खूंटी, सराइकेला, सिमडेगा	15
एसबीआई	देवघर, पाकुर, साहिबगंज, जामताड़ा, गढ़वा, लातेहर, पलामू	7
इलाहाबाद बैंक	दुमका व गोड्डा	2

उपरोक्त बैंको के अलावा निम्नलिखित ग्रामीण बैंको के शाखाओं द्वारा भी वित्तीय साक्षरता केन्द्र का सञ्चालन किया जाता है ,

झारखण्ड ग्रामीण बैंक - 15 केन्द्र ; **वनांचल ग्रामीण बैंक** - 9 केन्द्र
इसके अलावे झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक भी पिछले कुछ महीनों से 3 वित्तीय साक्षरता (रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम) केंद्र का संचालन कर रही है ।

जनवरी-मार्च 2018 तिमाही के दौरान आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर

तिमाही में आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर की संख्या	
वित्तीय साक्षरता केंद्र द्वारा	1214
ग्रामीण शाखाओं द्वारा	2157
कुल	3371

{रिपोर्ट-पृष्ठ संख्या-24 (a) एवं 24 (b) पर उपलब्ध है}

कार्यसूची सं	10
बैठक की तारीख	15.05.2018
बैठक संख्या	63

एसएलबीसी के विभिन्न उप समितियों के कामकाज

पहले के एसएलबीसी की बैठकों में लिए गए निर्णय के संदर्भ में, एसएलबीसी के निम्नलिखित उप-समितियां कार्य कर रही हैं। उप-समितियों से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:

एस.एल.बी.सी की उप समितियां

Sr. No	उप समिति के नाम	उप समिति के पदधारी	उप समिति के अन्य सदस्य	संदर्भ	पिछली बैठक की तिथि
1.	कृषि तथा संबद्ध उप समिति	प्रमुख सचिव / सचिव (कृषि) GOJ संयोजक - नाबार्ड	1) प्रमुख सचिव/ सचिव संस्थागत वित्त 2) प्रमुख सचिव/, सचिव जल संसाधन विभाग। 3) सचिव, वन विभाग। 4) नाबार्ड प्रमुख महाप्रबंधक या डीजीएम के स्तर के बराबर 5) संयोजक बैंक एसएलबीसी (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 6) एसबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 7) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 8) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या	1) कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां, (केसीसी सहित) 2) नई परियोजना/ स्कीम (कृषि) 3) कृषि ऋण देने के लिए क्षमता का विकास	09.05.2018

			डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 9) रजिस्ट्रार सहकारी समितियां		
2.	निर्यात संवर्धन	एसएलबीसी के संयोजक बैंक - संयोजक एसएलबीसी	1) प्रमुख सचिव /सचिव स्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन 2) भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग. एजीएम 3) स्थानीय निर्यात संस्था 4)उद्योग विभाग 5) एक्जिम बैंक 6)अन्य सदस्य बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई, और पीएनबी	1) निर्यात क्रेडिट के तहत ऋण देने की प्रगति की समीक्षा 2)हस्तकला /कृषि के निर्यात में सुधार के लिए सुझाव 3) निर्यात संवर्धन के लिए सक्षम कारकों का प्रोत्साहन	09.02.2018
3.	सुरक्षा	प्रमुख सचिव / सचिव (गृह) GOJ संयोजक- एसबीआई	1) एडीजी / पुलिस महानिरीक्षक – परिचालन 2) प्रमुख सचिव /सचिव स्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ 3) आरबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 4) संयोजक बैंक एसएलबीसी (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 5) एसबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि	1) बैंक के ट्रेजरी की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा 2) राज्य की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा / नक्सल क्षेत्र में विशेष रूप से चर्चा 3) बैंक डकैती के मामलों में अंतिम रिपोर्ट 4) बैंक शाखाओं / करेंसी चेस्ट में पुलिस बल की तैनाती	11.01.2018

			<p>6) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि)</p> <p>7) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि)</p> <p>8) झारखंड ग्रामीण बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि)</p>		
4.	सीडी अनुपात और एसीपी उप-समिति	एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक - एसएलबीसी	<p>1) प्रमुख सचिव /सचिव संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ.</p> <p>2) भारतीय रिजर्व बैंक</p> <p>3) नाबार्ड</p> <p>4) भारतीय स्टेट बैंक</p> <p>5) बैंक ऑफ इंडिया</p> <p>6) पंजाब नेशनल बैंक</p> <p>7) झारखंड ग्रामीण बैंक</p> <p>8) केनरा बैंक</p> <p>9)यूनियन बैंक</p>	<p>1) एसीपी की निगरानी उपलब्धि एवं अनुमानित सीडी अनुपात</p> <p>2) खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए विशेष रणनीति</p> <p>3) एसीपी के तहत ऋण देने में वृद्धि के लिए कारकों को सक्षम करने का विकास</p>	09.02.2018
5.	एसएलबीसी परिचालन समिति	एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक - एसएलबीसी	<p>1) संस्थागत वित्त विभाग</p> <p>2) भारतीय रिजर्व बैंक</p> <p>3) नाबार्ड</p> <p>4) निदेशक, उद्योग</p> <p>5) आईसीआईसीआई बैंक</p> <p>6) केनरा बैंक</p> <p>7) पंजाब नेशनल बैंक</p> <p>8) बैंक ऑफ इंडिया</p> <p>9) भारतीय स्टेट बैंक</p>	<p>1) नवीनतम स्थिति और सरकार /बैंकों के पास लंबित मुद्दें</p> <p>2) एसएलबीसी कामकाज में सुधार (बैंक /सरकार)</p>	09.02.2018

6.	विधानमंडल और अन्य मुद्दे पर उप समिति	सचिव, संस्थागत वित्त संयोजक-एसएलबीसी	<ol style="list-style-type: none"> 1) सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, सहकारी 3) सचिव, राजस्व 4) सचिव, कृषि 5) सचिव, योजना 6) भारतीय स्टेट बैंक 7) बैंक ऑफ इंडिया 8) इलाहाबाद बैंक 9) भारतीय रिजर्व बैंक 	विधानमंडल से संबंधित मुद्दों पर, राज्य में ऋण के माध्यम से विकास के लिए संशोधन और अन्य गतिविधियों के लिए राज्य सरकार एवं बैंकों से चर्चा	02.02.2015
7.	एमएसएमई और सरकार पर उप-समिति, प्रायोजित योजनाएं	सचिव, (ग्रामीण विकास) संयोजक-बीओआई	<ol style="list-style-type: none"> 1) सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, संस्थागत वित्त 3) सचिव, उद्योग 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक 	सरकार के तहत प्रायोजित योजनाओं में एमएसएमई वित्तपोषण और वित्तपोषण से संबंधित सभी मुद्दे,	19.02.2018 को RBI Empowered Committee on MSME की 37 वीं बैठक बुलायी गई थी।
8	आवास वित्त पर उप-समिति	सचिव (शहरी विकास) संयोजक-एसबीआई	<ol style="list-style-type: none"> 1) सचिव, शहरी विकास 2) सचिव, वित्त 3) राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रतिनिधि 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक 7) दोनों ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष 	आवास वित्त पोषण से संबंधित सभी मुद्दें (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र)	07.11.2017
9	SHG-Bank Linkage एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर उप-समिति	सचिव (ग्रामीण विकास) संयोजक - झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी	<ol style="list-style-type: none"> 1) प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, वित्त 3) भारतीय रिजर्व बैंक 4) एसएलबीसी 5) भारतीय स्टेट बैंक 6) बैंक ऑफ इंडिया 	आजीविका संवर्धन रणनीतियों पर राज्य स्तर समर्थन- झारखंड	11.05.2018

			<p>7) केनरा बैंक</p> <p>8) पी.एन.बी.</p> <p>9) झारखण्ड ग्रामीण बैंक</p> <p>10) नाबार्ड</p>		
10	RSETIs पर उप-समिति	सचिव (ग्रामीण विकास) संयोजक - झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी	<p>1) प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास</p> <p>2) सचिव, आईएफ और पीआई, GoJ</p> <p>3) भारतीय रिजर्व बैंक</p> <p>4) एसएलबीसी</p> <p>5) नाबार्ड</p> <p>6) भारतीय स्टेट बैंक</p> <p>7) केनरा बैंक</p> <p>8) पी.एन.बी.</p> <p>9) राज्य निदेशक, RSETI</p>	RSETI में प्रशिक्षण एवं उसके उपरांत बैंकों से Credit Linkage से सम्बन्धित मुद्दे	11.05.2018

कार्यसूची सं.	11
बैठक की तिथि	15.05.2018
बैठक सं.	63

विविध कार्यसूची

1. वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 25.09.2017 से 17.10.2017 तक देश के 50 विभिन्न स्थानों पर “मुद्रा प्रोत्साहन अभियान” कार्यक्रम का आयोजन किया गया था | इसके तहत रांची के मोरहाबादी मैदान में दिनांक 12.10.2017 को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें केंद्र सरकार की ओर से माननीय राज्य मंत्री, नागरिक उड्डयन विभाग, श्री जयंत सिन्हा जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे | इस कार्यक्रम में राज्य सरकार एवं वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार के वरीय अधिकारी भी उपस्थित थे | इस कार्यक्रम का आयोजन SLBC, झारखण्ड के द्वारा किया गया था एवं DFS के निर्देशानुसार कार्यक्रम के आयोजन में LIC द्वारा दी गई रु 10.00 लाख की सहयोग राशि के अतिरिक्त किये गए व्यय के आधार पर सभी प्रतिभागी बैंकों से रु 77400/- का contribution की मांग की गई थी | बैंकों के contribution की बात SLBC द्वारा कार्यक्रम के पूर्व में होने वाली बैठकों एवं mail के द्वारा सभी बैंको को दी गई थी | लगभग 07 माह बीत जाने एवं बार-बार लिखित एवं मौखिक आग्रह किये जाने के बावजूद अबतक 03 बैंक Axis Bank, ICICI Bank और IOB ने अब तक अपना contribution SLBC को प्रेषित नहीं किया है | यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है | इस forum के माध्यम से हम इन बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से यह आग्रह करते हैं कि यह राशि SLBC को अविलम्ब उपलब्ध करा दी जाये |

(Action: उपर्युक्त नामित सभी बैंक)

2. हाल ही में पूरे देश में (कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल को छोड़कर) ग्राम स्वराज अभियान का आयोजन किया गया जिसमें झारखण्ड राज्य में 252 गाँवों को चिन्हित कर बैंको को वहाँ के प्रत्येक व्यस्क के लिए PMJDY के अंतर्गत उनका खाता खोलवाने और उन्हें शत-प्रतिशत PMSBY एवं PMJJBY के अंतर्गत enroll करवाए जाने का लक्ष्य दिया गया था | झारखण्ड में 15 बैंको एवं 21 LDMs (गुमला, लोहरदगा एवं खूंटी को छोड़कर) को यह काम करना था | सभी बैंको एवं LDMs के अथक प्रयास के फलस्वरूप झारखण्ड राज्य ने अपने लिए सभी गाँवों में निर्धारित लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त कर लिया है | ये सभी बैंक एवं LDMs बधाई के पात्र हैं | हम सभी LDMs से यह आग्रह करते हैं कि इस उपलब्धि का Saturation Certificate निर्धारित परिपत्र में सभी वांछित अधिकारियों के हस्ताक्षर के साथ SLBC को अविलम्ब प्रेषित करें |

(Action: सभी LDMs)

3. RBI के circular FIDD.CO.LBS.BC No. 19/02.01.001/2017-18 दिनांक 06.04.2018 के अनुसार Lead Bank Scheme में काफी changes प्रस्तावित किये गए हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी सलंगन प्रतिलिपि में उपलब्ध है | बैंको से निम्नांकित बिंदुओं पर अपेक्षित ध्यान दिये जाने का आग्रह किया जाता है-

- i. To synchronize their internal business plans with ACP under Lead Bank Scheme,
- ii. Controlling heads should attend few of the BLBC meetings selectively,
- iii. Only authentic and system generated data should be feeded in the SLBC portal

(Action: सभी बैंक)

4. DFS द्वारा दिनांक 15.12.2017 एवं 19.12.2017 को भेजे गए मेल में पूरे झारखण्ड राज्य में जिलावार 5 KM के दायरे में 2764 गाँवों को चिन्हित किया गया है और वहाँ बैंकिंग outlet की जानकारी मांगी गई है कि वे गाँव बैंक शाखा अथवा BC से covered हैं या नहीं ? पुनः दिनांक 11.01.2018 को भेजे गए communication में BC के KO code, location address, mobile no तथा “क्या वे BC RBI के नये मानदंडों के अनुसार fixed location माने जा सकते हैं “ जैसी अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है | अभी तक केवल 17 LDMs द्वारा इसका रिपोर्ट SLBC को प्रेषित किया गया है | बार बार आग्रह किये जाने के बावजूद साहिबगंज LDMs द्वारा यह रिपोर्ट नहीं दिया गया है | इस रिपोर्ट से एक बात स्पष्ट हो रही है कि ज्यादातर जगहों पर RBI के मानदंडों के अनुसार fixed location BC नहीं है | पुनः इस रिपोर्ट के आधार पर सभी LDMs से वैसे सभी locations पर जहाँ कि न तो कोई बैंक की शाखा है और ना ही किसी बैंक द्वारा BC की नियुक्ति की गई है वहाँ पर अवस्थित निकटतम बैंक की जानकारी मांगी गई थी ताकि उन बैंको को वहाँ पर अविलम्ब BC की नियुक्ति के लिए निर्देश दिया जा सके, परंतु अभी तक किसी भी LDM द्वारा इसकी जानकारी नहीं दी गई है | SHG पर SLBC sub committee की दिनांक 09.02.2018 को हुई बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया है कि चूँकि अभी कई जगहों पर BC की नियुक्ति करनी पड़ेगी तो बैंकों द्वारा WSHG के members को BC agent के रूप में नियुक्त करने को प्राथमिकता दी जाये |

(प्रतिवेदन सलंगन)

(Action: सभी बैंक एवं LDMs)

5. DFS के पत्रांक 20/57/2010-FI दिनांक 22.11.2017 के द्वारा LWE जिलों में banking services के expansion के लिए झारखण्ड राज्य के पलामू एवं छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिलों को pilot जिलों के रूप में identify किया गया और वहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए banking outlets establish किये जाने की संभावनाओं को तलाशने के लिए जिला अधिकारियों के साथ बैठक किये जाने का सुझाव दिया गया था, ताकि इन जिलों की प्रगति के आधार पर अन्य LWE जिलों में इस व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके | इस सम्बन्ध में पलामू जिले में जिले के अधिकारियों द्वारा बैंको के साथ बैठक कर 06 स्थानों को चिन्हित कर बैंक की शाखाएँ खोले जाने का प्रस्ताव आया है | इन 06 स्थानों पर PNB, BOI, Andhra Bank

एवं SBI द्वारा शाखा खोला जाना है | SLBC द्वारा दिनांक 29.01.2018 को इस सम्बन्ध में इन बैंको एवं पलामू जिले के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में चिन्हित स्थानों पर बैंक शाखा खोलने हेतु संबंधित बैंक अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है | इन बैंको से आग्रह है कि इस सम्बन्ध में हुई प्रगति SLBC को अविलम्ब प्रेषित करें ताकि इसमें हुई प्रगति का ब्यौरा MHA एवं DFS को दिया जा सके |

Sr No	Identified locations/blocks	Proposed bank's name	Proposed place where branch may be opened
1	Naudiha Bazar	Punjab National Bank	Newly built Block Office premises
2	Pipra	Punjab National Bank	Newly built Block Office premises
3	Pandu	Bank of India	Block Office (under Construction)
4	Lalgarh Bihar	Andhra Bank	Railway Station
5	Ramgarh	State Bank of India	Panchayat Bhavan, Ramgarh
6	Untari Road	State Bank of India	Newly built Block Office premises

(Action: PNB, BOI, Andhra Bank एवं SBI)

6. दिनांक 07.02.2018 को DFS ने सभी SLBC को यह निर्देश दिया है कि APY को अलग agenda के रूप में रख कर इस पर विस्तृत विचार किया जाये और बैंको के performance की प्रगति पर गहन ध्यान दिया जाये | PFRDA द्वारा उपलब्ध कराये गए APY से संबंधित आंकड़े सलंगन है | जिन बैंको का enrollment प्रतिशत 50% से कम है, उनके नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसमें अपेक्षित सुधार करने का प्रयास करें |

(Action: सभी बैंक)

7. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किये गए आह्वान के मद्देनजर सभी बैंको से अपनी अपनी कार्यरत शाखाओं के आस पास के गाँवों को चिन्हित कर उन्हें digital village बनाये जाने का आग्रह किया गया था | इस दिशा में कुछ बैंको का प्रयास सराहनीय है परंतु अभी भी अन्य कई बैंको द्वारा इस दिशा में अपेक्षित कार्य किया जाना बाकी है | इससे संबंधित अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन सलंगन है |

(Action:

सभी बैंक)

8. DFS द्वारा राज्य में cash और ATMs की स्थिति की साप्ताहिक समीक्षा की जाती है | राज्य के सभी प्रमुख बैंको, खासकर वैसे बैंको से जिनके पास currency chest हैं, से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने से जुड़े किसी भी बैंक में cash की किल्लत ना होने दें और साथ ही सभी बैंको से आग्रह है कि वे नियमित रूप से अपने यहाँ के ATMs की निगरानी करें ताकि सभी ATMs तकनीकी रूप से सुचारु कार्य करते रहें और उनमें cash की कमी ना हो |

(Action: सभी बैंक)

कार्यसूची सं.	12
बैठक का दिनांक	15.05.2018
बैठक सं	63

Less cash/Digital बैंकिंग

- माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा less cash economy को बढ़ावा देने के लिए किये गए आहवाहन पर झारखण्ड राज्य ने त्वरित प्रतिक्रिया दिखाई और इसके तहत राज्य में digital transaction को लोकप्रिय बनाने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं-जिनमे Mobile App download करना और सभी नागरिकों को cashless transaction से जुड़े विभिन्न उत्पादों की जानकारी देना है। इसके साथ ही सभी इच्छुक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में POS machines देने की प्रक्रिया भी की जा रही है। राज्य के सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों/बैंकों द्वारा अपने जिले/बैंकों में इसके लिये नियमित प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों की बदौलत दिनांक 31.03.2018 तक राज्य में कुल 30078 POS machines का installation कराया जा चुका है जो demonetization के पूर्व यानि दिनांक 09.11.2017 तक केवल 6399 था। यद्यपि यह उपलब्धि संतोषजनक है परंतु इस दिशा में अभी और कार्य किये जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही सभी बैंको द्वारा पूरे राज्य में लगभग 3.61 लाख credit card, 1.84 करोड़ debit कार्ड, एटीएम, rupay कार्ड आदि और 22 लाख net banking की सुविधा अपने ग्राहकों को दी गई है।

{प्रगति प्रतिवेदन सलग्न-पृष्ठ सं-33 (a)}

कार्यसूची सं.	13
बैठक की तिथि	15.05.2018
बैठक सं	63

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा ...

64वीं SLBC बैठक की प्रस्तावित तिथि : 10 अगस्त 2018